



# IASBABA

One Stop Destination for UPSC/IAS Preparation

## 60 Days Week-1&2 Compilation



### DELHI

### BANGALORE

5B, Pusa Road, Karol  
Bagh, New Delhi -110005.  
Landmark: Just 50m from  
Karol Bagh Metro Station,  
GATE No. 8 (Next to  
Croma Store)  
Ph:0114167500

#1737/37, MRCR Layout, Vijaynagar  
Service Road, Vijaynagar, Bangalore  
560040. PH: 09035077800 /  
7353277800



[support@iasbaba.com](mailto:support@iasbaba.com)



[www.iasbaba.com](http://www.iasbaba.com)

**Q.1) भारतीय संविधान में उल्लिखित शब्द 'संप्रभु' (Sovereign) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. इसका तात्पर्य यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी का डोमिनियन है तथा इसे पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है।
2. भारत या तो विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का हिस्सा दे सकता है।
3. राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभु स्थिति को सीमित करती है, जहां यह सदस्यता ब्रिटिश राजा / रानी को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकार करती है।

**नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही विवरण चुनें**

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2
- d) उपरोक्त सभी

**Q.1) Solution (c)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
<p>भारत को एक संप्रभु इकाई घोषित करके, प्रस्तावना पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता पर जोर देती है। 'संप्रभु' शब्द का तात्पर्य है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र का एक निर्भरता है और न ही एक डोमिनियन है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है।</p>	<p>एक संप्रभु राज्य होने के नाते, भारत या तो एक विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का हिस्सा दे सकता है।</p>	<p>1949 में, भारत ने राष्ट्रमंडल की अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की तथा ब्रिटिश क्राउन को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया।</p> <p>हालाँकि, कुछ आलोचकों का कहना है कि 'राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत राष्ट्र की संप्रभु स्थिति को सीमित करती है, जहाँ तक यह सदस्यता ब्रिटिश राजा / रानी को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकार करती है। हालाँकि, यह दृष्टिकोण सही नहीं है। राष्ट्रमंडल अब ब्रिटिश राष्ट्रमंडल नहीं है। 1949 से यह संप्रभु समान मित्रों का संघ रहा है, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक संबंधों के कारण, सहकारी</p>

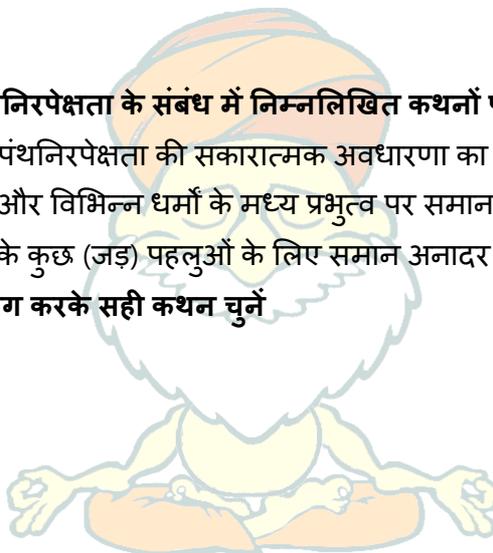
		<p>प्रयासों के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए राष्ट्रमंडल में हाथ मिलाना पसंद किया है। भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता एक स्वैच्छिक कार्य और एक शिष्टाचार व्यवस्था है। राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में ब्रिटिश राजा / रानी का भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं है। भारत उसके प्रति कोई निष्ठा नहीं रखता है। "ब्रिटिश राजा राष्ट्रमंडल संघ का एक प्रतीकात्मक प्रमुख है।" (नेहरु)</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Q.2) भारत में प्रचलित पंथनिरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. भारतीय संविधान पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है।
2. यह अंतर-धार्मिक और विभिन्न धर्मों के मध्य प्रभुत्व पर समान ध्यान केंद्रित करता है।
3. यह स्थापित धर्मों के कुछ (जड़) पहलुओं के लिए समान अनादर की अनुमति देता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

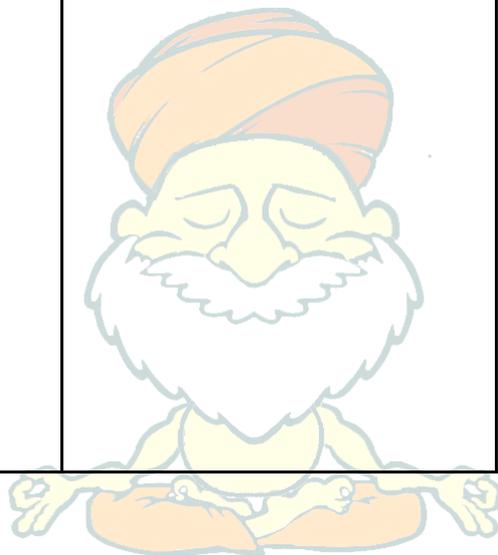
- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी



**Q.2) Solution (d)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
<p>भारतीय संविधान पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है, अर्थात् हमारे देश में सभी धर्म (चाहे उनकी संख्या कुछ भी हो) को राज्य से समान दर्जा और</p>	<p>भारतीय पंथनिरपेक्षता ने एक ऐसे रूप में एक अलग रूप धारण किया, जो पहले से मौजूद समाज में धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के मध्य में था। इसने अंतर-धार्मिक और विभिन्न धर्मों के मध्य</p>	<p>भारतीय पंथनिरपेक्षता की जटिलता की "सभी धर्मों के लिए समान सम्मान" वाक्यांश द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है। यदि इस वाक्यांश का अर्थ सभी धर्मों या परस्पर सहसंबंधों के शांतिपूर्ण सह-</p>

<p>समर्थन प्राप्त है।</p>	<p>प्रभुत्व पर समान ध्यान केंद्रित किया। भारतीय पंथनिरपेक्षता ने समान रूप से दलितों और महिलाओं के हिंदू धर्म के भीतर उत्पीड़न, भारतीय इस्लाम या ईसाई धर्म के भीतर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त किया तथा आश्वस्त किया कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों के लिए कोई खतरा नहीं खड़ा कर सकता है।</p>	<p>अस्तित्व से है, तो यह पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि पंथनिरपेक्षता केवल शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व या भोगवाद से कहीं अधिक है। यदि इस वाक्यांश का अर्थ सभी स्थापित धर्मों और उनकी प्रथाओं के प्रति सम्मान की समान भावना है, तो एक अस्पष्टता है जिसे समाशोधन की आवश्यकता है। भारतीय पंथनिरपेक्षता सभी धर्मों में सैद्धांतिक रूप से राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देती है। इस तरह के हस्तक्षेप से हर धर्म के कुछ पहलुओं का अनादर होता है। उदाहरण के लिए, भारतीय पंथनिरपेक्षता के भीतर धार्मिक रूप से स्वीकृत जाति-पदानुक्रम स्वीकार्य नहीं हैं। पंथनिरपेक्ष राज्य को हर धर्म के हर पहलू को समान सम्मान के साथ व्यवहार नहीं करना पड़ता है। यह स्थापित धर्मों के कुछ पहलुओं के लिए समान अनादर की अनुमति देता है।</p>
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Q.3) भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं का मिलान उन स्रोतों से करें जिनसे ये लिए गए हैं

1. राष्ट्रपति के चुनाव की विधि	a. ब्रिटिश संविधान
2. न्याय का विचार	b. सोवियत संविधान
3. उपराष्ट्रपति का पद	c. अमेरिकी संविधान
4. मौलिक कर्तव्य	d. आयरिश संविधान

5. कैबिनेट प्रणाली

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- 1-d, 2-c, 3-c, 4-b, 5-a
- 1-d, 2-b, 3-c, 4-b, 5-a
- 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-a
- 1-c, 2-b, 3-d, 4-b, 5-a

Q.3) Solution (b)

विशेषताएं	स्रोत
राष्ट्रपति के चुनाव की विधि	आयरिश संविधान
प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का आदर्श	सोवियत संविधान (USSR, अब रूस)
उप-राष्ट्रपति का पद	अमेरिकी संविधान
मौलिक कर्तव्य	सोवियत संविधान (USSR, अब रूस)
कैबिनेट प्रणाली	ब्रिटिश संविधान

Q.4) पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- इसने पहली बार गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य को अलग किया।
- इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विभेद किया।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य

1853 का चार्टर अधिनियम, पहली बार, गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करता है। इसने गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में छह नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ने, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विभेद किया। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया। इस प्रकार, इसने दोहरी सरकार की एक प्रणाली स्थापित की।

**Q.5) निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम, 1935 का हिस्सा नहीं थीं?**

1. इसने प्रांतों में द्विसदनीयता (bicameralism) प्रदान की।
2. इसने प्रांतों में द्वैधशासन (dyarchy) अपनाने के लिए प्रावधान किया।
3. इसने तीन सूचियों-संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया, जिसमें प्रांतीय सूची में अधिकतम संख्या में विषय थे।

**नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें**

- a) केवल 1
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

**Q.5) Solution (c)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
इसने ग्यारह प्रांतों में से छह में द्विसदनीयता का परिचय दिया। इस प्रकार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधानसभाओं को एक विधान परिषद (उच्च सदन) और एक विधान सभा (निम्न सदन) से युक्त द्विसदनीय बनाया गया। हालांकि, उन पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे।	इसने प्रांतों में द्वैधशासन को समाप्त कर दिया तथा इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की। इसने केंद्र में द्वैधशासन अपनाने का प्रावधान किया।	अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों के संदर्भ में विभाजित किया- संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 विषयों के साथ), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, 54 विषयों के साथ) और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषयों के साथ)।

Q.6) निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया था?

1. इसने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया।
2. इसने ब्रेटन वुड्स संस्थान में भारत की सदस्यता की पुष्टि की।
3. इसने पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य संकल्प को अपनाया।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- a) केवल 1
- b) 1 और 2
- c) 1 और 3
- d) 2 और 3

Q.6) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
संविधान सभा स्वतंत्र भारत (डोमिनियन लेजिस्लेचर) की पहली संसद बन गई। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में हुई, इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की तथा जब यह विधायी निकाय के रूप में मिले, तो इसकी अध्यक्षता जी वी मावलंकर ने की थी।	भारत ब्रेटन वुड्स प्रणाली का सदस्य बन गया था, जबकि यह अभी भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था।	22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था।

Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारतीय क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र शामिल हैं।
2. 1975 में, केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला।
3. भारतीय राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3
- c) केवल 3
- d) उपरोक्त सभी

## Q.7) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	सत्य
<p>'भारत के क्षेत्र' में केवल राज्य ही नहीं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और वो क्षेत्र भी शामिल हैं, जिन्हें भविष्य के किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं तथा केंद्र के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित प्रदेश, सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं।</p>	<p>1947 में, ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद, सिक्किम भारत का 'संरक्षक' राज्य बन गया, जिससे भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा, बाहरी मामलों और संचार की जिम्मेदारी संभाली। 1974 में, सिक्किम ने भारत के साथ अधिक सहयोग की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार, 35 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1974) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ के 'सहयोगी राज्य' का दर्जा देकर संविधान के तहत राज्य का एक नया वर्ग प्रस्तुत किया। 36 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1975) को सिक्किम को भारतीय संघ (22 वां राज्य) का पूर्ण राज्य बनाने के लिए लागू किया गया था। यह कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था।</p>	<p>भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक के रूप में कार्य करता है।</p>

## Q.8) भारत में राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. किसी को 'राज्य' का दर्जा प्रदान करना, या, 'राज्य' का दर्जा छीन लेना, अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है।
2. अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य के रूप में जाना जा सकता है।
3. भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3
- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

**Q.8) Solution (b)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
<p>अनुच्छेद 4 यह घोषणा करता है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना (नए अनुच्छेद के तहत) तथा नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम (अनुच्छेद 3 के तहत) के परिवर्तन के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधनों के रूप में नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है कि ऐसे कानून एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किए जा सकते हैं।</p> <p>आप उन उदाहरणों पर भी विचार कर सकते हैं जहाँ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बनाया गया था, और राज्यों को केन्द्र शासित प्रदेश (J &amp; K) बनाया गया था, वे संविधान में संशोधन नहीं थे।</p>	<p>बेरुबरी यूनियन केस (1960) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने के लिए संसद की शक्ति (अनुच्छेद 3 के तहत) एक विदेशी देश द्वारा भारतीय क्षेत्र के अधिग्रहण को कवर नहीं करती है। इसलिए, भारतीय क्षेत्र को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके केवल एक विदेशी राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। नतीजतन, 9 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1960) को उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।</p>	<p>सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में निर्णय सुनाया कि, भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इसमें किसी विदेशी देश द्वारा भारतीय क्षेत्र का अधिग्रहण शामिल नहीं है।</p>

**Q.9) भारत में नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. भारत में जन्म लेने वाले शरणार्थियों के बच्चों को भारतीय नागरिक माना जाता है।
2. यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, तो उसके सभी नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं।

3. भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चे और विदेशी शत्रु जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- 1 और 2
- 2 और 3
- केवल 3
- उपरोक्त सभी

**Q.9) Solution (c)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	सत्य
वर्तमान भारतीय राष्ट्रियता कानून काफी हद तक जस सेंगुईनिस (jus sanguinis) (वंश द्वारा नागरिकता) का पालन करता है, जो कि जस सोली ( jus soli) (क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार से नागरिकता) के विपरीत है।	यदि कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, तो भारत सरकार उन लोगों को निर्दिष्ट करती है जो क्षेत्र के लोगों में से हैं, वे भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बन गया, तो भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता (पांडिचेरी) आदेश, 1962 जारी किया।	भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चे और विदेशी शत्रु जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं।

**Q.10) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

- भारत में, चाहे वे जिस भी राज्य में पैदा हुए हों या निवास करते हों, सभी नागरिक पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं तथा उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
- जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, तो उस व्यक्ति का नाबालिग बच्चा अपनी भारतीय नागरिकता नहीं खोता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1

- b) केवल 2  
c) 1 और 2 दोनों  
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.10) Solution (d)**

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
<p>भारत में, चाहे वे जिस भी राज्य में पैदा हुए हों या निवास करते हों, सभी नागरिक पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं तथा उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हालाँकि, भेदभाव की अनुपस्थिति का यह सामान्य नियम कुछ अपवादों के अधीन है,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संसद (अनुच्छेद 16 के तहत) उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ नियोजन या नियुक्तियों के लिए एक शर्त या उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के रूप में एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास आवश्यक कर सकती है।</li> <li>• संविधान (अनुच्छेद 15 के तहत) किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, न कि निवास के आधार पर।</li> <li>• आवागमन और निवास की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 के तहत) किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के अधीन है।</li> </ul>	<p>जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। हालाँकि, जब ऐसा बच्चा अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तो वह भारतीय नागरिकता फिर से आरंभ कर सकता है।</p>

**Q.11) नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची के साथ-साथ इनर लाइन परमिट शासन वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।

2. यह अधिनियम भारत में किसी भी देश के उन छह धर्मों के लोगों के लिए 12 वर्ष के निवास के प्रावधान को शिथिल करके 6 वर्ष करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.11) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
नागरिकता (संशोधन) विधेयक (CAB) संविधान की छठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा - जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त आदिवासी बहुल क्षेत्रों से संबंधित है। यह विधेयक उन राज्यों पर भी लागू नहीं होगा जिनके पास इनर-लाइन परमिट शासन है (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम)।	1955 के अधिनियम के तहत, प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के लिए आवश्यकताओं में से एक यह है कि आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान, तथा पिछले 14 वर्षों में से 11 के लिए भारत में रहना चाहिए था। संशोधन अधिनियम इस 11 साल की आवश्यकता को समान छह धर्मों और तीन देशों से संबंधित व्यक्तियों के लिए 5 साल तक के लिए छूट देता है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों के अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करते हुए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दिसंबर 2014 से पहले उत्पीड़न से भाग गए थे।

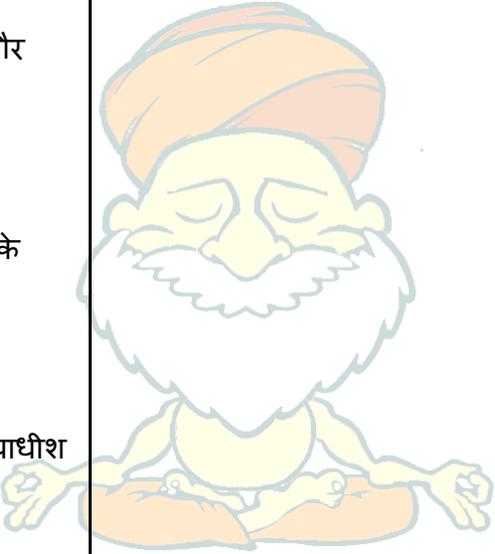
Q.12) निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की किसी अनुसूची में शामिल नहीं है?

- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान।
- मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
- भूमि सुधारों से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- 1 और 2
- केवल 1
- केवल 2
- 2 और 3

## Q.12) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
<p>दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और इसी तरह से संबंधित प्रावधान हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत के राष्ट्रपति</li> <li>2. राज्यों के राज्यपाल</li> <li>3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष</li> <li>4. राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष</li> <li>5. राज्यों में विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष</li> <li>6. राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष</li> <li>7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश</li> <li>8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश</li> <li>9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक</li> </ol>	<p>छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं।</p> 	<p>नौवीं अनुसूची में भूमि सुधारों और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन तथा अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के कानूनों से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13 लेकिन वर्तमान में 282) शामिल हैं।</p>

## Q.13) भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ओसीआई, पंजीकृत ओसीआई व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है।
2. पंजीकृत ओसीआई सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भारत के नागरिक पर प्रदत्त अधिकारों का हकदार नहीं होगा।
3. उनके पास कृषि या वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में गैर-निवासी भारतीयों (NRI) के साथ समानता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2

- b) 1 और 3  
c) 2 और 3  
d) उपरोक्त सभी

## Q.13) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
ओसीआई को 'दोहरी नागरिकता' के रूप में माने जाने की गलती नहीं करना चाहिए। ओसीआई राजनीतिक अधिकारों को प्रदान नहीं करता है।	भारत के पंजीकृत प्रवासी नागरिक, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भारत के नागरिक को प्रदत्त अधिकारों के हकदार नहीं होंगे।	भारत के एक पंजीकृत प्रवासी नागरिक को भारत में आने के लिए कई प्रवेश, बहुउद्देश्यीय, जीवन-कालीन वीजा दिया जाता है, उसे भारत में किसी भी लम्बे प्रवास के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण से छूट दी जाती है, तथा उसे सामान्य 'गैर-निवासी भारतीयों (NRI) की तरह कृषि, वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में।' समान अधिकार हैं, जो मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विशिष्ट लाभ / समता अधिसूचित किए जाते हैं।

भारत की प्रवासी नागरिकता (OCI) योजना अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों (PIO) के प्रवासी नागरिक (OCI) के रूप में पंजीकरण के लिए प्रावधान प्रदान करती है, जो भारत के नागरिक 26 जनवरी, 1950 या उसके बाद या 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे या नहीं, सिवाय जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा है या ऐसे अन्य देश जिन्हें केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें।

Q.14) भारत और ब्रिटेन द्वारा सरकार के संसदीय रूप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएँ साझा की जाती हैं?

1. संसद की संप्रभुता
2. दोहरी कार्यकारी (Dual executive)
3. सामूहिक उत्तरदायित्व
4. गणतंत्रवादी प्रणाली

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3
- c) 1 और 4
- d) 3 और 4

Q.14) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	सत्य	सत्य	असत्य
ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि संसद भारत में सर्वोच्च नहीं है तथा एक लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियों का आनंद लेती है	दोनों देशों में दोहरी कार्यकारी है। राष्ट्रपति नाममात्र के कार्यकारी (de jure executive or titular executive) होते हैं जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी (de facto executive) होते हैं।	दोनों देशों में सामूहिक उत्तरदायित्व है, जहां मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।	ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है तथा एक लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियों का आनंद लेती है।

Q.15) राष्ट्रपति प्रणाली के स्थान पर सरकार के संसदीय स्वरूप को वरीयता देने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं?

1. स्थिर सरकार
2. उत्तरदायी सरकार

3. शक्तियों का पृथक्करण
4. व्यापक प्रतिनिधित्व

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 2 और 4
- b) 1, 2 और 3
- c) 2, 3 और 4
- d) उपरोक्त सभी

Q.15) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	सत्य	असत्य	सत्य
संसदीय प्रणाली अस्थिर सरकार की ओर ले जाती है।	उत्तरदायी सरकार संसदीय प्रणाली का प्रमुख लाभ है।	संसदीय प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है तथा इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है	संसदीय प्रणाली विभिन्न समूहों से व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।

Q.16) भारत में क्षेत्रीय परिषदों (Zonal councils) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से स्थापित की गयी हैं।
2. केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद् के अध्यक्ष होते हैं।
3. क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में से एक तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्ति की वृद्धि पर रोक लगाना है।

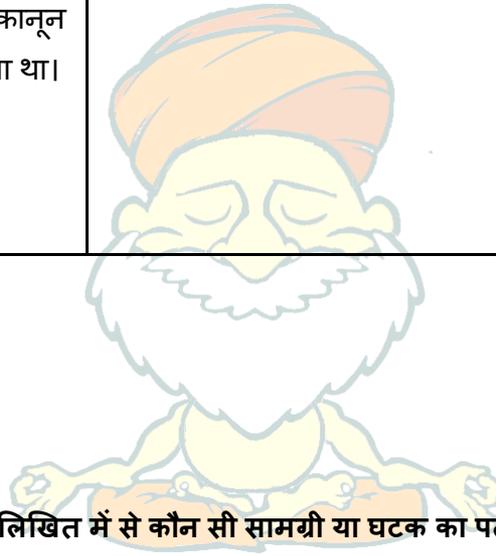
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.16) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3

असत्य	सत्य	सत्य
<p>पांचों क्षेत्रीय परिषदें - पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य - राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राज्यों के बीच अंतर-राज्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थीं। उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना 1971 में भारत के सात उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं से निपटने के लिए की गई थी। इसे उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 नामक कानून के तहत स्थापित किया गया था।</p>	<p>केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद् के अध्यक्ष होते हैं।</p>	<p>क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• राष्ट्रीय एकीकरण लाना;</li> <li>• तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्ति की वृद्धि पर रोक लगाना;</li> <li>• केंद्र और राज्यों को विचारों और अनुभवों का सहयोग तथा आदान-प्रदान करने के लिए सक्षम करना;</li> <li>• विकास परियोजनाओं के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना।</li> </ul>



Q.17) प्रस्तावना से निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री या घटक का पता चलता है -

1. संविधान के अधिकार का स्रोत
2. भारतीय राज्य की प्रकृति
3. संविधान के उद्देश्य
4. संविधान को अपनाने की तिथि

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 2 और 3
- b) 1, 3 और 4
- c) 2, 3 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q.17) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	सत्य	सत्य

प्रस्तावना में चार अवयवों या घटकों का पता चलता है:

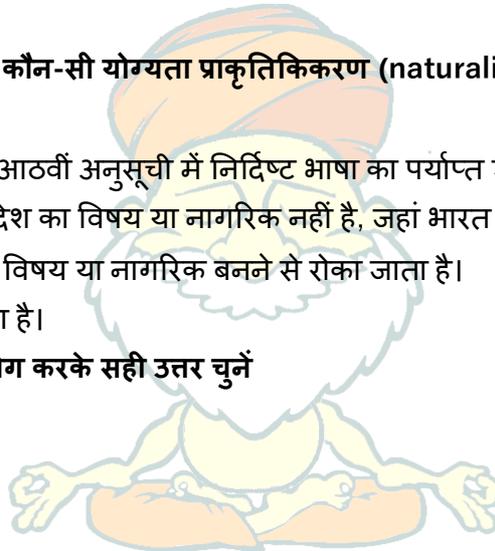
- संविधान के अधिकार का स्रोत: प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपने अधिकार प्राप्त करता है।
- भारतीय राज्य की प्रकृति: यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राजनीति की घोषणा करता है।
- संविधान के उद्देश्य: यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करता है।
- संविधान को अपनाने की तिथि: इसमें तिथि के रूप में 26 नवंबर, 1949 निर्धारित है।

**Q.18) निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यता प्राकृतिककरण (naturalization) द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता है?**

1. उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान है।
2. वह किसी भी ऐसे देश का विषय या नागरिक नहीं है, जहां भारत के नागरिकों को प्राकृतिक रूप से उस देश का विषय या नागरिक बनने से रोका जाता है।
3. वह अच्छे चरित्र का है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी



**Q.18) Solution (d)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य

केंद्र सरकार, किसी आवेदन पर, किसी भी व्यक्ति के लिए प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है (अवैध प्रवासी नहीं होने पर) यदि उसके पास निम्न योग्यताएँ हैं:

(a) वह किसी भी देश का विषय या नागरिक नहीं है, जहां भारत के नागरिकों को प्राकृतिक रूप से उस देश का विषय या नागरिक बनने से रोका जाता है;

- (b) यदि वह किसी भी देश का नागरिक है, तो वह भारतीय नागरिकता स्वीकार किए जाने के लिए आवेदन करने की स्थिति में उस देश की नागरिकता का त्याग करने का वचन देता है;
- (c) वह या तो भारत में रहता है या भारत में एक सरकार की सेवा में है या आंशिक रूप से पहले में है और आंशिक रूप से दूसरे में है, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो;
- (d) यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, या आंशिक रूप से पहले में है और आंशिक रूप से दूसरे में है, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ;
- (e) वह अच्छे चरित्र का है;
- (f) कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान है, और
- (g) कि उसे दिए गए प्राकृतिककरण के प्रमाण पत्र की स्थिति में, वह भारत में निवास करने का इरादा रखता है, या एक सेवा के तहत सेवा में प्रवेश करना या जारी रखना चाहता है।
- भारत में सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत, जिसका सदस्य भारत है या भारत में स्थापित सोसइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय है।

**Q.19) निम्नलिखित में से कौन-सी ऐसी स्थितियाँ हैं जो किसी को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित करने के लिए उत्तरदायी हैं?**

1. धोखे से नागरिकता प्राप्त करना।
2. युद्ध के दौरान शत्रु के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार।
3. राजद्रोह के आरोपों (Sec124A) के तहत दर्ज (Booked) किया गया हो।

**नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें**

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

**Q.19) Solution (a)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य

वंचितता (Deprivation) भारतीय नागरिकता का अनिवार्य समापन है  
केंद्र सरकार, यदि:

राजद्रोह के आरोपों का लगना नागरिकता वंचित करने का आधार नहीं है।

<p>(a) धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की है:</p> <p>(b) नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्टा दिखाई है:</p> <p>(c) नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया है;</p> <p>(d) नागरिक को पंजीकरण या प्राकृतिककरण के बाद पांच वर्ष के भीतर किसी भी देश में दो साल तक कैद में रखा गया है; तथा</p> <p>(e) नागरिक सात वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहा है।</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Q.20) संविधान सभा की समितियों के साथ निम्नलिखित व्यक्तित्वों का मिलान उनके द्वारा किया गया**

समितियां	व्यक्तित्व
1. राज्यों के लिए समिति	a. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
2. प्रांतीय संविधान समिति	b. डॉ. के.एम. मुंशी
3. प्रक्रिया नियम समिति	c. जवाहर लाल नेहरू
4. कार्य संचालन समिति	d. सरदार पटेल

**नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें**

- a) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a
- b) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b
- c) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
- d) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

**Q.20) Solution (d)**

समिति	व्यक्तित्व
1. राज्यों के लिए समिति	जवाहर लाल नेहरू

2. प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
3. प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
4. कार्य संचालन समिति	डॉ. के.एम. मुंशी

**Q.21) मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. ये निगमों या कंपनियों के लिए भी उपलब्ध हैं।
2. ये निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।
3. ये पवित्र (sacrosanct) या स्थायी हैं।

**नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें**

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

**Q.21) Solution (a)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
उनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं चाहे नागरिक, विदेशी या कानूनी व्यक्ति जैसे निगम या कंपनियां।	उनमें से अधिकांश राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध, कुछ अपवाद जैसे कि राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध और निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। जब राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार केवल निजी व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन किए जाते हैं, तो कोई संवैधानिक उपचार नहीं होते हैं, केवल सामान्य कानूनी उपचार होते हैं।	वे पवित्र या स्थायी नहीं हैं। संसद उन्हें कम कर सकती है या निरस्त कर सकती है लेकिन केवल एक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तथा इसे एक साधारण अधिनियम द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह संविधान के 'बुनियादी ढांचे' को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है।

**Q.22) निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' माना जाता है?**

1. पंचायतें और नगर पालिकाएँ
2. ओएनजीसी

3. एनसीईआरटी
4. न्यायपालिका

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1,2 और 3
- c) 1,2 और 4
- d) उपरोक्त सभी

Q.22) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	असत्य
ऐसा कोई भी प्राधिकरण जिसके पास कोई भी कानून बनाने, किसी भी आदेश को पारित करने, विनियमन और उपनियम बनाने, आदि की शक्ति है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड और अन्य वैधानिक, संवैधानिक निकाय राज्य की परिभाषा में आते हैं।	वैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय जो सरकार से वित्तीय संसाधन प्राप्त करते हैं, उन पर सरकार का समुचित नियंत्रण होता है तथा कार्यात्मक चरित्र जैसे कि ICAR, CSIR, ONGC, IDBI, विद्युत् बोर्ड, NAFED, दिल्ली परिवहन निगम आदि राज्य की परिभाषा में आते हैं।	वैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय जो आमतौर पर सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं होते हैं, वे राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। उदाहरण स्वायत्त निकाय, सहकारिता, एनसीईआरटी आदि हैं।	न्यायपालिका राज्य नहीं है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, महाराष्ट्र और Anr v. के मामले में इस प्रश्न का उत्तर दिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 'न्यायालय' की परिभाषा में प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते समय या प्रशासनिक क्षमता में निर्णय लेते समय, केवल "राज्य" शामिल हैं तथा न्यायिक पक्ष पर नहीं।

Q.23) भारतीय प्रणाली पर कानून के नियम (Rule of law) के निम्नलिखित में से कौन से अवयव लागू हैं?

1. मनमानी शक्ति का अभाव
2. कानून के समक्ष समानता

3. व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 3
- उपरोक्त सभी

**Q.23) Solution (a)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य

कानून के नियम की अवधारणा में निम्नलिखित तीन तत्व या पहलू हैं:

- मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति, अर्थात् कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है।
- कानून के समक्ष समानता, अर्थात् सभी नागरिकों (अमीर या गरीब, उच्च या निम्न, आधिकारिक या गैर-आधिकारिक) की समान अधीनता जो सामान्य कानून न्यायालयों द्वारा प्रशासित भूमि के सामान्य कानून के लिए हो।
- व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता, अर्थात् संविधान व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, जो कि कानून के न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किया जाता है बजाय कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है।

पहला और दूसरा तत्व भारतीय प्रणाली पर लागू होते हैं तथा तीसरा नहीं। भारतीय प्रणाली में, संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है।

**Q.24) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

- उचित प्रतिबंध लगाने के लिए अपराध हेतु मानहानि और उकसाना एक आधार है।
- अकेले कार्यकारी कार्रवाई द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

**Q.24) Solution (a)**

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाने के आधार पर वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभ्यास पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।	उचित प्रतिबंधों की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: (1) उनके तहत प्रतिबंध केवल या किसी कानून के अधिकार के तहत लगाया जा सकता है: कोई कार्यकारी प्रतिबंध अकेले बिना किसी कानून का पालन किए नहीं लगाया जा सकता है। (2) प्रत्येक प्रतिबंध उचित होना चाहिए। (3) प्रतिबंध 19 (2) से (6) में उल्लिखित उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए।

**Q.25) विदेश यात्रा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है**

- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 22

**Q.25) Solution (c)**

अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।  
अनुच्छेद 19 देश के भीतर आवागमन अधिकार की रक्षा करता है।

**Q.26) शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

- इसे 2002 के 86 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
- यह संविधान में सम्मिलित होने वाला मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी पहला ऐसा प्रावधान था।
- यह अधिकार नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों, दोनों के लिए उपलब्ध है।

**नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें**

- 1 और 2
- 1 और 3
- 2 और 3
- उपरोक्त सभी

**Q.26) Solution (b)**

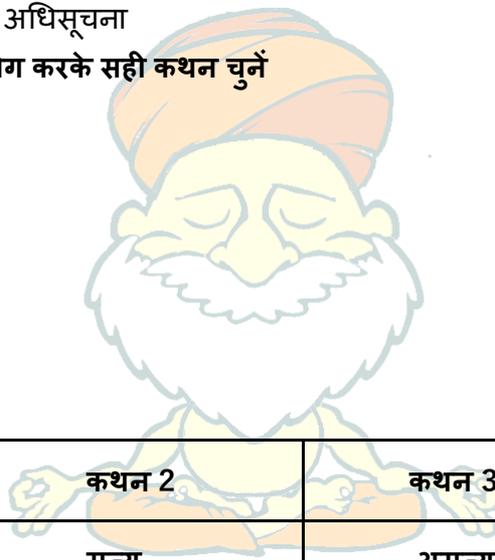
कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 A) प्रावधान 2002 के 86 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।	इस संशोधन से पहले भी, संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था।	यह नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों, दोनों के लिए भी उपलब्ध है।

Q.27) निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 13 के तहत 'कानून' (Law) माना जा सकता है?

1. अध्यादेशों
2. नागा प्रथागत कानून (Naga customary laws)
3. संवैधानिक संशोधन
4. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1,2 और 3
- c) 1,2 और 4
- d) उपरोक्त सभी



Q.27) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	सत्य
राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों द्वारा जारी किए गए अध्यादेश जैसे अस्थायी कानून को अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाता है।	कानून के गैर-विधायी स्रोत, अर्थात्, कानून की शक्ति वाले कस्टम या मान्यता को अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाता है।	अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि एक संविधान संशोधन कानून नहीं है और इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में कहा कि एक संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह एक	अनुच्छेद 13 के तहत आदेश, उपनियम, नियम, विनियमन या अधिसूचना जैसे प्रत्यायोजित विधान (कार्यकारी कानून) की प्रकृति में वैधानिक उपकरण को कानून माना जाता है।

		मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो संविधान के 'बुनियादी ढांचे' का एक हिस्सा है तथा इसलिए, इसे शून्य घोषित किया जा सकता है।	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Q.28) भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. इसमें एक व्यक्ति को दूसरे के धर्म में परिवर्तन का अधिकार शामिल है।
2. इसके तहत, राज्य हिंदू धार्मिक संस्थानों के सुधार के लिए प्रावधान प्रदान कर सकता है।
3. इस अधिकार के तहत आने वाले हिंदुओं में सिख, पारसी, जैन और बौद्ध शामिल हैं

**नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें**

- a) 1 और 2
- b) केवल 2
- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

**Q.28) Solution (b)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	असत्य
इसमें दूसरों में धार्मिक विश्वासों का प्रसारण और प्रसार या किसी के धर्म के सिद्धांतों को उजागर करना शामिल है। लेकिन, इसमें किसी अन्य व्यक्ति को एक व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन सभी व्यक्तियों को समान रूप से 'अंतश्चेतना की स्वतंत्रता' को प्रतिबंधित करता है।	राज्य को सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक वर्गों के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और समूहों के लिए सुधार प्रदान करने की अनुमति है।	इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं

Q.29) निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है / हैं?

1. समान काम के लिए समान वेतन
2. गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
4. पर्यावरण का संरक्षण और सुधार

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 3 और 4
- c) केवल 4
- d) 1,2 और 3

Q.29) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	असत्य	सत्य	सत्य
पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (d) एक समाजवादी सिद्धांत है।	समान न्याय को बढ़ावा देना तथा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 A) एक समाजवादी सिद्धांत है।	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए (अनुच्छेद 46) एक गांधीवादी सिद्धांत है।	पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए (अनुच्छेद 48 A) एक उदार-बौद्धिक सिद्धांत है।

Q.30) निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित है?

1. 42 वां संशोधन अधिनियम: आय, पदस्थिति (status), सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना
2. 44 वां संशोधन अधिनियम: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना
3. 86 वां संशोधन अधिनियम: सभी बच्चों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल तथा शिक्षा, जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2

- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) 2 और 3

**Q.30) Solution (c)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	सत्य
1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने नए निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा, जिससे राज्य को आय, पदस्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है (अनुच्छेद 38)।	उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने हेतु 1976 के 42 वें संशोधन अधिनियम ने निर्देशक सिद्धांत, (अनुच्छेद 43 A) जोड़ा।	2002 के 86 वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदल दिया, जिससे राज्य को सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।

**Q.31) निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए किया गया है?**

1. बाल और किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम
2. मातृत्व लाभ अधिनियम
3. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन
4. आपराधिक प्रक्रिया संहिता

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1,2 और 3
- c) 1,2 और 4
- d) उपरोक्त सभी

**Q.31) Solution (d)**

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	सत्य	सत्य
बाल और किशोर श्रम	महिला श्रमिकों के हितों	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड,	आपराधिक प्रक्रिया

निषेध तथा विनियमन अधिनियम, (1986) को बच्चों और श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है।	की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) और समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) बनाया गया है।	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, हथकरघा बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, कॉयर बोर्ड, रेशम बोर्ड आदि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए स्थापित किए गए हैं।	संहिता (1973) ने राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Q.32) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत दिए गए निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं हैं?

1. देश की रक्षा करना
2. करों का भुगतान करना
3. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना
4. वोट देना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1,2 और 4
- b) 2,3 और 4
- c) 2 और 4
- d) उपरोक्त सभी



Q.32) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	सत्य	असत्य	सत्य
देश की रक्षा करना अनुच्छेद 51 A (d) के तहत एक मौलिक कर्तव्य है।	करों का भुगतान करने की विशेषता एक मौलिक कर्तव्य नहीं है।	सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 A (i) के तहत एक मौलिक कर्तव्य है।	वोट डालने की विशेषता कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है

Q.33) मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारतीय संविधान विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों की एक सूची है।
2. इनमें नैतिक कर्तव्यों के साथ-साथ नागरिक कर्तव्य दोनों शामिल हैं।

3. वे कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 3
- उपरोक्त सभी

Q.33) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
जापानी संविधान, संभवतः, विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों की एक सूची शामिल है।	उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को बनाए रखना एक नैतिक संकल्पना है तथा संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है।	वे कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इसलिए, संसद उनमें से किसी को पूरा करने में विफलता के लिए उचित जुर्माना या सजा का प्रावधान कर सकती है।

Q.34) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं, क्योंकि उनके लिए राज्य को कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है।
- निर्देशक सिद्धांतों को उनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है तथा वे स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं।
- मौलिक अधिकार सदैव निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभावी होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- 1 और 3
- केवल 2
- 2 और 3
- उपरोक्त सभी

Q.34) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3

असत्य	सत्य	असत्य
मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति हैं क्योंकि वे राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं।	निर्देशक सिद्धांतों को उनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है तथा वे स्व-चालित रूप से लागू नहीं होते हैं।	मौलिक अधिकार आमतौर पर निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभावी होते हैं। इसके अपवाद हैं, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 39 (b) और (c) में निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धांतों के अधीनस्थ के रूप में स्वीकार किया गया था।

Q.35) पुट्टस्वामी अधिनिर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निजता का अधिकार किसके अंतर्गत सुरक्षित है

1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 19
3. अनुच्छेद 21

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी



Q.35) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और Anr. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो मानता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत निजता के अधिकार को एक मौलिक संवैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है।

Q.36) निम्नलिखित में से किस कानून को अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने और अमान्य होने से बचाया गया है?

1. निगमों का समामेलन (Amalgamation of corporations)
2. निगमों के शेयरधारकों के अधिकारों में संशोधन
3. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण
4. राज्य द्वारा संपत्तियों का प्रबंधन संभालना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1, 2 और 4
- b) 1, 3 और 4
- c) 2 और 4
- d) उपरोक्त सभी

Q.36) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	सत्य

अनुच्छेद 31A कानून की पाँच श्रेणियों को चुनौती देता है तथा अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों के समान संरक्षण) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 19 (भाषण, सभा, आवागमन आदि के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देता है। वे कृषि भूमि सुधार, उद्योग और वाणिज्य से संबंधित हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (a) राज्य द्वारा संपत्ति और संबंधित अधिकारों का अधिग्रहण;
- (b) राज्य द्वारा संपत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण;
- (c) निगमों का समामेलन;
- (d) निगमों के निदेशकों या शेयरधारकों के अधिकारों का शमन या संशोधन; तथा
- (e) खनन पट्टों की निकासी या संशोधन।

जब राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (अनुच्छेद 30) की संपत्ति का अधिग्रहण करता है, तो उसे मुआवजा प्रदान करना होगा।

Q.37) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अनुच्छेद 35 राज्य सूची में निर्दिष्ट मामलों पर एक कानून बनाने के लिए संसद की क्षमता को विस्तृत करता है।
2. अनुच्छेद 35 राज्य विधायिका को कुछ मामलों पर कानून बनाने के लिए प्रतिबंधित करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1

- b) केवल 2  
c) 1 और 2 दोनों  
d) न तो 1 और न ही 2

## Q.37) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
अनुच्छेद 35, उपरोक्त निर्दिष्ट मामलों पर एक कानून बनाने के लिए संसद की क्षमता का विस्तार करता है, भले ही उन मामलों में से कुछ राज्य विधानसभाओं (यानी, राज्य सूची) के दायरे में आ सकते हैं।	अनुच्छेद 35 कहता है कि कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित होगी तथा राज्य विधानसभाओं में नहीं।

Q.38) अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान प्रदान करता है, जब मार्शल लॉ भारतीय क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में लागू हो। मार्शल लॉ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. 'मार्शल लॉ' की व्याख्या को संविधान में 'एक क्षेत्र में सेना के शासन' के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. मार्शल लॉ की घोषणा के परिणाम स्वरूप बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का निलंबन हो जाता है।
3. यह सरकार और सामान्य कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2  
b) 2 और 3  
c) केवल 3  
d) उपरोक्त सभी

## Q.38) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	सत्य
'मार्शल लॉ' शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। शाब्दिक रूप में, इसका	सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है कि मार्शल लॉ की घोषणा के कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के अधिकार को	यह सरकार और सामान्य कानून न्यायालयों को निलंबित करता है।

अर्थ 'सैन्य शासन' है।	निलंबित नहीं किया जा सकता है।	
-----------------------	-------------------------------	--

**Q.39) उत्प्रेषण (certiorari) रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है**

1. न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण
2. प्रशासनिक अधिकारी
3. वैधानिक निकायों (Legislative bodies)

**नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें**

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3
- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

**Q.39) Solution (a)**

<b>कथन 1</b>	<b>कथन 2</b>	<b>कथन 3</b>
<b>सत्य</b>	<b>सत्य</b>	<b>असत्य</b>

<p>पहले, उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती थी, न कि प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध। हालांकि, 1991 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है।</p>	<p>उत्प्रेषण विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है।</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

**Q.40) अनुच्छेद 28 चार प्रकार के शिक्षण संस्थानों के बीच अंतर करता है। धार्मिक निर्देश**

**निम्नलिखित में से किसमें पूरी तरह से निषिद्ध है?**

1. राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थान
2. राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएँ
3. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान
4. राज्य द्वारा प्रशासित संस्थान लेकिन किसी धर्मस्व (endowment) या ट्रस्ट के तहत स्थापित।

**नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें**

- a) केवल 1
- b) 1 और 2
- c) 1,2 और 4

d) उपरोक्त सभी

Q.40) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	असत्य	असत्य	असत्य

इस प्रकार, अनुच्छेद 28 चार प्रकार के शैक्षिक संस्थानों के बीच अंतर करता है:

- (a) राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित किए गए।
  - (b) राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी धर्मस्थ (endowment) या ट्रस्ट के तहत स्थापित।
  - (c) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।
  - (d) राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएँ।
- (a) में धार्मिक निर्देश पूरी तरह से प्रतिबंधित है जबकि (b) में, धार्मिक निर्देश की अनुमति है। (c) और (d) में, स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक निर्देश की अनुमति है।

Copyright © by IASbaba

*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of IASbaba.*